

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 33 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, मंगलवार ,03 अगस्त 2021 , मूल्य रु. 1.50

संक्षिप्त समाचार

नीतिश सरकार में काम करना
चुनौतीपूर्ण : सप्लाइ चौधरी

पटना, (एजेंसी)। बिहार की नीतिश सरकार में मंत्री और बीजेपी के बिरुद नेता सप्लाइ चौधरी ने एनडीए गठबंधन की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। औरंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि बिहार में जो हम गठबंधन की सरकार चलाना काफी चुनौती भरा काम है। चौधरी ने कहा कि बिहार में जो हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और वहां हमारी सरकार स्वतंत्र नहीं है, इसके बिना हमें विभिन्न तरह की चुनौतियों का समाप्ति पड़ रहा है। सप्लाइ चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह जहां सिर्फ हमारी सरकार है, वहां हम किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

जीका वायरस की दस्तक से अलर्ट मोड पर सरकार

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद केन्द्र सरकार के तीन सदस्यीय टीम महाराष्ट्र भेजी है। वह टीम राज्य सरकार के साथ मिलकर इस वायरस की रोकथाम के लिए स्थिति की निगरानी करेगी। इसके अतिरिक्त जीवी स्तर पर राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में जीका वायरस के मामले केरल में भी पाए गए थे। केरल के बाद रविवार को महाराष्ट्र में जीका के मरीज मिलने से सरकार अलर्ट है।

दरअसल महाराष्ट्र में रविवार को जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला पुणे जिले में सामने आया था।

लक्षक-ए-तैयबा के टेरर मांडूल का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में आतंकी बाद पर लगातार प्रहर जारी है। इनी कड़ी में जम्प-कश्मीर पुलिस ने अनंतनगर में लक्षक-ए-तैयबा के आतंकी मॉडूल का भांडाफोड़ किया है और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनपर आरोप है कि वे अनंतनगर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर के इलाके के युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे।

जीवनकारी के मुताबिक, जिन चार लोगों को पकड़ा गया है वे युवाओं के मन में जहां घोलकर उन्हें लक्षक-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को जोड़न करने के लिए उकसाते थे।

कार्टून

ON LINE टूटी

एंटनी बिल्कन और जयशंकर के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन ने अपने दो दिवसीय बायर यात्रा के दौरान हिंदू-प्रशांत क्षेत्र में भारीयी की बढ़ावा देने और कोरोना इम्बारी से निपटने के प्रयासों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। वहाँ ऐसी जानकारी है कि विदेश मंत्री जयशंकर और एंटनी बिल्कन के बीच हुई वार्ता में मौजूदा कारोबारी रिश्तों को लेकर कुछ तल्ख मुद्दे भी उठे।

बिल्कन ने मोदी सरकार की प्रस्तावित ई-



सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

कारोबारी रिश्तों को लेकर तल्ख मुद्दे उठे।

उठे।

बिल्कन ने मोदी

सरकार की

प्रस्तावित

ई-

संपादकीय

भीख की मजबूरी

भीख मांगने वालों के प्रति जिस श्रेष्ठ संवेदना का प्रदर्शन देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है, वह न केवल स्वागत-योग्य है, बल्कि अनुकरणीय भी है। अदालत ने दोटूक कह दिया कि वह सड़कों से भिखारियों को हटाने के मुद्दे पर एलीट या संभ्रंशत वर्ग का नज़रिया नहीं आजाएगी, व्यापौक भीख मांगना एक समाजिक और अर्थिक समस्या है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रघड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की बेंच ने कहा कि वह सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से भिखारियों को हटाने का आदेश नहीं दे सकती, व्यापौक शिक्षा और रोजगार की कमी के चलते बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लोग आमतौर पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। अदालत का इशारा साफ था कि भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं होगा और इससे भीख मांगने की समस्या का समाधान नहीं होगा। याधिकारकों को शायद उम्मीद थी कि सर्वोच्च अदालत सड़कों-चौराहों पर लोगों को भीख मांगने से रोकने के लिए कोई आदेश या निर्देश दीजि। अदालत ने समस्या की व्याख्या जिस संवेदना के साथ की है, वह गरीबी हटाने की दिशा में आगे के फैसलों के लिए बहुत गौरतलब है। अदालत ने पूछा कि आखिर लोग भीख खायेंगे हैं? गरीबी के कारण ही यह रिश्ते बनती है।

यह सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि सङ्कों पर कोई भिखारी न दिखे, लेकिन सङ्कों से भिखारियों को हटाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? क्या जो लाचार है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं, क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? जरिट्स चंद्रचूल ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील चिन्मय शर्मा से यह भी कहा कि कोई भीख नहीं मांगना चाहता। मतलब, सरकार को भीख मांगने की समस्या से अलग ढंग से निपटना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार असंख्य भारतीयों तक नहीं पहुंच पार ही है। मुख्यधारा से छिट्के हुए वंचित लोग भीख मांगने को विवश हैं। ऐसे लोगों तक जल्दी से जल्दी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। जहां तक चौराहों पर भीख की समस्या है, तो स्थानीय प्रशासन इस मामले में कदम उठा सकता है। सङ्क पर भीख मांगने वालों को सचेत किया जा सकता है कि वे किसी सुरक्षित जगह पर ही भीख मांगने जैसा कृत्य करें। भीख मांगना अगर सामाजिक समस्या है, तो समाज को भी अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। समाज के आर्थिक रूप से संपत्र और सक्षम लोगों को स्थानीय स्तर पर सरकार के साथ मिलकर भीख जैसी मजबूरी का अंत करना चाहिए। बहरहाल, सर्वोच्च अदालत ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भिखारियों और बेघर लोगों के पुनर्वास और टीकाकरण का आग्रह करने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके उंचित ही जवाब मांगा है। याचिका की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसमें महामारी के बीच भिखारियों और बेघर लोगों के पुनर्वास, उनके टीकाकरण, आश्रय व भोजन उपलब्ध कराने का प्रशंसनीय आग्रह किया गया है। वाकई भीख मांगने वाले और बेघर लोग भी कोविड-19 के संबंध में अन्य लोगों की तरह यिकिसा सुविधाओं के हकदार हैं। केंद्र सरकार के साथ तथा राज्य सरकारों को स्वास्थ्य और रोजगार का दायरा बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बेघर, निर्धन हैं, उन तक मानवीयता का एहसास पुरजार पहुंचे।

यह चिंताजनक हिंसा

पूर्वोत्तर के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसा असाधारण और अत्यंत गंभीर है। इस हिंसा में असम के पांच पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। वास्तविकता यह है कि इन दो पड़ोसी राज्यों के बीच खूनी संघर्ष लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद और उससे पैदा हुए टकराव की परिणति है। हिंसा की तर्कीयों को देखकर लग रहा था कि किसी एक सप्रभु देश के 2 प्रांत नहीं, बल्कि दो दुश्मन राष्ट्रों के बीच हिंसा हो रही है। हिंसा की प्रकृति को संरेखानिक और संरक्षणात् गतिरोध के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। हिंसक झटप के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा के बीच टिवटर युद्ध शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थिता के बाद दोनों शांत हुए। पूर्वोत्तर में सीमा विवाद की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा विवाद का तनाव ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से विरासत के रूप में मिला है। आजाद भारत में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सीमाओं से संबंधित गलतियों को दुरुस्त करने का अवसर था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मिजोरम 1972 में संघ शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले यह असम का हिस्सा था। असम का नगालैंड, मेघालय और अरुणाचल के साथ भी सीमा विवाद है। अतीत में भी पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा विवाद को लेकर टकराव होते रहे हैं। विवादों को सुलझाने के लिए प्रयास भी किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। असम-मिजोरम के बीच हिंसक झटप आंखें खोलने वाली है। यह घटना बताती है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच सीमा विवाद कितना गंभीर हो सकता है। असम और मिजोरम दोनों ने लंबे समय तक अशांति और उथल-पुथल का सामना किया है। अब वहाँ आर्थिक पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से पूर्वोत्तर बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इसलिए पूर्वोत्तर के राज्यों के नेताओं को शांतिपूर्ण ढंग से सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों के बीच सीमा विवाद आपसी सहयोग से सुलझाए जाते हैं। केंद्र राज्यों के आंतरिक मामलों में केवल मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है।

ਇਹਾਂ ਭੀ ਸੰਸਦ, ਰਖਾ ਭੀ ਸੰਸਦ

इधर भी संसद है, उधर भी संसद है। लेकिन जिधर देखो, उधर संसद, कि यहां-वहां सब जगह संसद ही संसद नहीं है। ऐया, सेंट्रल विस्टारा गाली संसद बनने में भी अभी वक्त है। फिर संसद के अलावा विधानसभाएं भी तो हैं और वहां मरम्मती भी बदले जा रहे हैं। उनका रुदन भी है। रुटने वाले का नहीं।

पिटने वाले का रुदन। इधर भाजपा को ताथे के पते फेंटने का शैक्षणिक चरण्या है। कभी इसे कांग्रेस का शागम माना जाता था, आज भाजपा है। लोग इसे भाजपा का कांग्रेसीकरण भी मान सकते हैं। पर कहीं यह न हो जाए कि इस शैक्षणिक के चलते जैसे कांग्रेस के दिन लद, वैसे ही भाजपा के भी दिन भी लद जाएं। टाइम पास के लिए पते पीटना भी कुछ-कुछ उसी कहावत का विस्तार है कि बैठा बनिया क्या करे, इधर के बाट उधर करे। फिर भी संसद है और इधर है और उधर भी है। दोनों एक दूसरे के दरवाजे पर हैं। इसे फोन कॉलवाली वह दूरी मत समझ लेना, जब प्रधानमंत्रीजी ने कहा था कि सरकार बिना किसानों से फोन कॉल की दूरी पर है। यह दूरी आठ महीने में तो खत्म हुई नहीं, आगे की भगवान जाने। खेर, सीन पड़ोसियों वाला ही है। एक-दूसरे के लिए कोसने हैं, लानत-मलामत हैं, शिकवे-शिकायत हैं। जो संसद है और जो वास्तव में संसद है, उसमें खूब हो हल्ला है, जिसमें कुछ लोग जूतम पैजार कहने की हृद तक जा सकते हैं। अलबत्ता जो मंत्री पद पाने से रह गए वे यह भी कह सकते हैं कि जूतों में दाल बंट रही है। फिर याहे चिराग पासवान से पूछकर देख लीजिए ये नीतीशर्जी। विरोधी हैं तो क्या हुआ, दर्द तो एक है न। उन्होंने दर्द एक-दूसरे को जरूर दिया होगा, लेकिन एक-दूसरे की दवा करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं लग रहे। और साहब दवा को लेकर तो विपक्ष पहले ही इतना बवाल खड़ा किए हुए है। सरकार को चाहिए कि जैसे उसने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से काई मौत नहीं हुई, वैसे ही हय दवा भी कर दे कि दवा की कमी से कोई मौत नहीं हुई। बौमारी से हुई हो तो हुई हो। खेर, उस संसद में बड़ा हल्ला है साहब, जासूसी तक को लेकर है। लेकिन उधर बगल वाली संसद में कार्रवाई बड़ी शार्ति से चलती है। न कोई हो हल्ला होता है, न कार्रवाई स्थगित होती है। मुद्दों पर चर्चा होती है, बहस होती है। बस जो वास्तव में संसद है, वहां इतने मुद्दे हैं कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती और इस संसद में ले-देकर कर एक ही मुद्दा है-कृषि कानून वापस लो। फिर भी खूब चर्चा है।

दुनिया बदल सकती है यह दोस्ती

जनवरी, 2021 में जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की संपत्ति लेने के बाद यह तीसरा मौका था, जब अमेरिकी सरकार का कोई वरिष्ठ नेता भारत आया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन कल देर शाम नई दिल्ली से कुवैत की ओर रगाना हो चुके हैं, लेकिन उनसे पहले रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जलवायु परिवर्तन मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी की भारत यात्रा यह संकेत दे चुकी है कि बाइडन सरकार नई दिल्ली को कितनी अहमियत दे रही है। बिल्कन का यह दौरा द्विपक्षीय सर्वधों के साथ-साथ क्षेत्रीय रिश्तों की दशा-दिशा तय करने वाला माना जाएगा। हिंद

प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कहीं अधिक मजबूती से मिलकर काम करने की सहमति बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान बातीत का केंद्र रहा, यद्योंकि अमेरिका जिस तरह से वहाँ से निकला है, उससे भारत भी चिंतित है। रात के अंधेरे में अमेरिकी सेनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ा और हवाई जहाज से वे अपने देश के लिए रवाना हुए। भले ही अमेरिका ने अफगान हुक्मत को इसके बारे में स्पष्ट कर दिया था, लेकिन छिपते-छिपाते अमेरिकी फौज की रवानगी कई एशियाई देशों को वियतनाम युद्ध की याद दिला गई। सन 1975 में साइर्झॉन (हो ची मिन्ह शहर) से अमेरिकी फौज अपने दामन पर हार का दाग लेकर इसी तरह लौटी थी। अफगानिस्तान से उसकी घर वापसी को भी कई देश इसी रूप में देख रहे हैं। भारत के साथ दिक्षित यह है कि अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे के निर्माण और व्यापार परियोजनाओं में उसने तकरीबन तीन अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने वहाँ के सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। चूंकि वहाँ अब तक कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं हो सका है और तालिबान अपने प्रभाव क्षेत्र के लगातार बढ़ने का दावा कर रहा है, इसलिए नई दिल्ली इन विकास-कार्यों के भविष्य को लेकर चिंतित है। एक तर्क यह दिया जा सकता है कि तालिबान शायद इन परियोजनाओं को नुकसान न पहुंचाए, मगर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के बारे में दुष्प्रचार कर रहा है और अमेरिकी फौज की वापसी को भारत की हार के रूप में दुष्प्रचारित कर रहा है, उससे खतरा यह है कि कहीं पाकिस्तानपरस्त आतकवादी तालिबान की आड़ में इन विकास-कार्यों के लिए खतरा न बन जाए। नई दिल्ली वाशिंगटन से यह भरोसा चाहता है कि वह अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देने के बजाय एक ठोस रणनीति के तहत उसकी मदद करता रहे।

भारत और अमेरिका के रिश्ते में 'क्वाड' भी काफी अहमियत रखता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना यह संगठन अभी भले ही वैधानिक जामा नहीं पहन सका है, लेकिन इसने धीन के साथ तनाव बढ़ाने पर अपनी सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को तेजी से मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। मार्च, 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसकी एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें

A medium shot of a man in a dark suit and tie standing in front of a white aircraft. He is smiling and waving his right hand towards the camera. To his left is the side of the aircraft, which has a large circular seal featuring an eagle and other symbols. The background is a clear blue sky.

होगा और भारत में कथित मानवधिकार हनन का भी। मगर ये ऐसे मसले हैं, जो हरेक बातचीत का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन इन पर काई खास गंभीरता नहीं दिखाई जाती। अलबता, अमेरिका में भारतवर्षियों को होने वाली दिक्षा अब आपसी बातचीत का मुख्य मसला बनती जा रही है। अमेरिका की बीजा नीति पर भारत सवाल उठाता ही रहता है, अब अनिवासी भारतीयों पर होने वाले नस्तीय हमले भी चिंता की दृजह बन गए हैं। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ किसी तरह की शारीरिक या भावनात्मक हिंसा नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि बाइडन प्रशासन भी इस दिशा में संजीदा है और अनिवासी भारतीयों ही नहीं, तमाम प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह रहा है। कुल मिलाकर, लिंकन को यह यात्रा कई मायनों में उल्खेनीय साथित हुई है। विदेश मंत्री बनने के बाद वह पहली बार भारत आए थे और यहां उन्होंने बाइडन प्रशासन का यह मंत्र देहराया कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अच्छी बात है कि भारत सरकार की तरफ से भी उर्ध्वं सकारात्मक जवाब मिला है। दोनों देशों की यह जु़गलबंदी आने वाले दिनों में वैश्विक व्यवस्था को कई रूपों में प्रभावित कर सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

(घ लखफ क अपन पिपार ह

भारतीय भाषाओं के मोर्चे पर सकारात्मक पहल



भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई ने हिंदी, बागला, मराठी, मलयालम समेत 11 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराए जाने को मंजूरी दी दी है। इसी तरह मेडिकल के दाखिले के लिए हाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंड्रेस टेस्ट भी 13 भारतीय भाषाओं में कराए जाने का फैसला लिया गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के चलते भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई करके आए बच्चों का तनाव बढ़ जाता था। उन्हें समझने में दिक्षित होने लगती थी। दागरकी तरफ से सरकार ने इसका बदला लाया।

था। इससे उपर्युक्त तात्पुरा से कई बार हताशा में कृछु बच्चे ने अपनी जान तक दे दी थी। कई पढ़ाई छोड़ने के मजबूर होते रहे हैं तो कई हताशा में पढ़ाई में पिछड़ते चले गए हैं।
नयी शिक्षा नीति ने भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम बनाने की जो रूपरेखा रखी है, उसके मुताबिक एआईसीटीई और मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया के आगे बढ़ना मामूली बात नहीं है। भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई या दाखिल परीक्षा होने की राह नयी शिक्षा नीति से ही संभव हुआ है।

हिमालयवासियों की जमीन बचानी होगी

चाहिए। राज्यपाल के लिए। कुछ भी अशोभनीय बोलने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौ बार सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा



केवल एक सूखे या एक राज्य की भी नहीं है। बात है लोकतंत्र, संविधान, संसदीय ढाँचे, शिक्षाचार, समझदारी

और साझेदारी की। चाहे राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र की अनुमति नहीं देने का मामला हो, चाहे विधानसभा भवन में राज्यपाल के प्रवेश के रोक का मामला हो वाहे जिलाधिकारियों के साथ बैठक की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय के उपकूलपतियों से चर्चा की बात हो। ये तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जो शायद केवल बंगल में ही हुए हैं, और मौजूदा राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान ही हुए। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने भी दर्जनों बार राज्यपाल पर सरकारी काम में बेवजह दखल देने और भाजपा के

एजेंट की तरह काम करने का आरोप भी लगाया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच काफी सङ्घर्ष नजर आया था, लेकिन वह पहला और आखिरी मौका था और उसके बाद दोनों की बीच दूरिया बढ़ती गई। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच लगातार चौड़ी होती खाई लोकतंत्र के हित में नहीं है। राजनीति के पड़ित कहते हैं-3ब राज्यपाल और राज्य सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री खूल कर एक टूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इससे संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा बढ़ रहा है।

